

विचार बिन्दु

विश्व इतिहास में प्रत्येक महान और महत्त्वपूर्ण आन्दोलन

उत्साह द्वारा ही सफल हो पाया है। –एमर्सन

सुशासन के लिए अधिक आवश्यक क्या - नियम या नीयत?

भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। यहां पर अनेक प्रकार के कानून, नियम, प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश बने हुए हैं। इन सबके उपरांत भी अभी तक भारत में असमानता इतनी अधिक क्यों है? सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ वांछित, वंचित वर्ग तक क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन अधिक फल फूल रहा है?

सरकार का हर निर्णय इसी कथित उद्देश्य से लिया जाता है कि उससे भ्रष्टाचार कम होगा और आम जन को अपने कार्य करवाने में सुविधा मिलेगी। उसे अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वास्तव में ऐसा होता किसी को दिखाई नहीं देता। यहां तक कि जैसे-जैसे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन बढ़ता गया, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार भी कम होने के स्थान पर बढ़ता गया।

सरकार के सभी विभागों की समान स्थिति है, चाहे वे आधारभूत संरचना के निर्माण में लगे हों, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रदान करने के काम में लगे हों, गरीबी उन्मूलन के कार्य में लगे हों या सामाजिक कल्याण और न्याय की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के काम में लगे हों। सरकार ने बजट की कमी के कारण यह तय किया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको देने के स्थान पर केवल गरीब लोगों की पहचान करके उन्हें ही लाभान्वित किया जाय। इस उद्देश्य से 197८ में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई तो गांव के पांच सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके योजनाओं का लाभ उन्हें देने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह निर्णय गांव के लोगों के समक्ष लिया जाता था, अधिकांशतया वही लोग अंत्योदय परिवारों में चयनित किए गए जो वास्तव में गरीब थे। इस योजना का लाभ भी बड़ी सीमा तक निर्धन व्यक्तियों तक पहुंचा।

बाद में जब बीपीएल योजना प्रारंभ हुई तो उसमें बहुत सारे मापदंड बना दिए गए जिनके आधार पर सर्वे किया गया और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी पी एल) लोगों की सूची बनाई गई। जब बीपीएल में चयनित लोगों को लाभ देने का प्रश्न आया तो देखा गया कि कई प्रभावशाली और अपेक्षाकृत संपन्न व्यक्ति भी बीपीएल की सूची में सम्मिलित हो गए। जो वास्तव में गरीब थे और जिनकी कोई पहुंच सरकारी अधिकारियों तक नहीं थी, उनमें से अधिकांश सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। इसके लिए योजना को दोष नहीं दिया जा सकता अपितु जिन लोगों ने बीपीएल का सर्वे किया उनकी नीयत सही नहीं थी। यदि वे गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मानसिकता रखते, तो सरकारी धन का दुरुपयोग होने से बचा जा सकता था ।

यही हाल सरकार द्वारा गरीबों को 5 किलो राशन बांटने की योजना का हो रहा है । ये समाचार लगातार पढ़ने में आते हैं कि कई आयकर दाता भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं । ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति का पता न हो । किंतु जब उनकी नीयत ही ठीक नहीं है तो फिर उसका लाभ भी गलत लोगों को ही मिलेगा। नीयत का प्रश्न तब अधिक प्रासंगिक होता है जब चयनित व्यक्तियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना हो, जबकि उसके पात्र उससे कहीं अधिक संख्या में हों । जो व्यक्ति अपने प्रभाव के कारण गरीबों की सूची में सम्मिलित हो जाएंगे वे लाभ लेने में सबसे आगे रहेंगे और वास्तविक वंचित व्यक्ति उसी स्थिति में रह जाएंगे।

परिवहन विभाग में जब लाइसेंस देने का काम ऑनलाइन नहीं हुआ था, तब शायद कई लोग बिना एजेंट की सहायता से भी अपना लाइसेंस परिवहन कार्यालय में जाकर बनवा लेते थे। अब, जब से ऑनलाइन लाइसेंस बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ है तब से एजेंट व्यवस्था समाप्त होने के स्थान पर और मजबूत हो गई है। जब विभाग यह दावा करता है कि घर बैठे आप सारा काम कर सकते हैं तो अधिकांश लोग एजेंटों से काम करवाने हेतु क्यों मजबूर हैं? कारण स्पष्ट है, ऑनलाइन व्यवस्था ऐसे बनेर है कि उस पर काम करना ही संभव नहीं है। सस्का मुख्य कारण विभागियों अधिकारियों को विकृत मानसिकता ही है। अधिकांश सरकारी अधिकारी केवल टाइम पास करने या पैसा बनाने की नीयत से ही सरकारी नौकरी में आते हैं।

स्थायी निकाय जैसे जेडीए, यूआरटी, नगर निगम आदि से अधिकांश नागरिकों का वास्ता पड़ता है। सब काम जैसे नक्शा पास कराना हो, किसी व्यापार का लाइसेंस लेना हो, कन्वर्शन कराना हो वह संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की 'सेवा पूजा' किए बगैर संभव नहीं है। हमारे एक मित्र ने एक नगर निगम में जब भू उपयोग परिवर्तन का प्रार्थना पत्र दिया तो उस पर 7० बार आपत्तियां लगाई गईं। उनसे कहा गया कि आप 1० लाख रुपए एजेंट को देते तो आपका काम तत्काल हो सकता था। यह सब दोष नियमों का नहीं केवल मात्र नीयत का है। अधिकांश विभागों में जहां ऑनलाइन की व्यवस्था है, वहां का पोर्टल काम ही नहीं करता। यही हाल हेल्प लाइन नंबर का है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सरकारी काम में न पैसे की कमी आडे आती है न नियमा जो बात आडे आती है, वह है अधिकारियों की नीयत।

नरगा में भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से सारे कामों की सूची ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध की गई। इसके बावजूद नरगा देश की भ्रष्टतम योजना में से एक बनकर रह गई है, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। इस कानून में प्रवधान है कि 15 दिन में काम न मिलने पर ग्रामीण को बेरोजगारी

जिस गति से आजकल सरकार द्वारा निर्मित भवन, सड़क और पुल टूट रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि तकनीक में बहुत अधिक विकास के बावजूद इंजीनियरों/अधिकारियों की खराब नीयत के कारण ऐसा हो रहा है। चूंकि हर काम में अधिकारियों/इंजीनियरों द्वारा कमीशन लिया जाता है। स्वीकृत राशि का बहुत कम हिस्सा वास्तव में काम पर खर्च होता है।

भत्ता मिलना चाहिए यह सभी को पता है कि नाम मात्र के लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वे यह सिद्ध कर सकें कि उन्होंने किस तिथि को काम के लिए आवेदन किया था? स्थिति और विकट तब हो जाती है जब जिनके पास शिकायत करनी होती है, वही इस भ्रष्टाचार के दुष्पन्न में भागीदार हो जाते हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में तो नीयत का महत्व सबसे अधिक है। शिक्षा में संख्यात्मक विस्तार और गुणत्मक सुधार के नाम पर कंप्यूटर के माध्यम से 'दर्पण' 'डाइस', 'अपार' जैसे सॉफ्टवेयर बनाए गए ताकि बच्चों की संख्या और उनके

स्तर का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सके। किंतु वास्तविकता यह है कि इससे शिक्षा के स्तर का कतई संबंध नहीं है। इसके विपरीत शिक्षकों का पूरा समय डेटा एंटी करने में ही निकल जाता है। जहां पहले ही शिक्षक कम हो, वहां इस अनावश्यक काम में लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। आज का दसवीं पास विद्यार्थी तीन चार दशक पूर्व के पांचवी पास विद्यार्थी की अपेक्षा भाषा और गणित को जानकारी में कहीं पीछे है। इस प्रकार, आज का स्नातक, कुछ दशक पहले के हाई स्कूल के समकक्ष भी नहीं है। किसी की नीयत शिक्षा में सुधार करना नहीं अपितु केवल कागजी खाना पूर्ति मात्र रह गया है। नियमानुसार 75% से कम उपस्थिति वाले बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा सकता, किंतु यह सर्व ज्ञात है कि किसी भी सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 1०-20% भी नहीं रहती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इसी मानसिकता के कारण कोचिंग व्यवसाय फलफूल रहा है।

सरकार ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कई विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय आदि खोलने की घोषणा तो कर दी किंतु उसकी नीयत वास्तव में शिक्षा प्रदान की नहीं थी। यदि वास्तव में ऐसा होता तो पहले वे उपयुक्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करते । आज कई ऐसे 12वीं के विद्यालय हैं जहां विषयों के शिक्षक नहीं हैं । मेडिकल कॉलेजों में उन्ही शिक्षकों को हर जगह निरीक्षण के समय दिखा दिया जाता है। जो शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों को मान्यता देने के नाम पर कई प्रकार के प्रमाण पत्र लेता है, उसी के स्वयं के विद्यालय छत ढह जाने से कई बच्चों की जान ले लेते हैं। खराब नीयत के लिए जवाबदेही की कमी भी बहुत बड़ा कारण है।

जिस गति से आजकल सरकार द्वारा निर्मित भवन, सड़क और पुल टूट रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि तकनीक में बहुत अधिक विकास के बावजूद इंजीनियरों/अधिकारियों की खराब नीयत के कारण ऐसा हो रहा है। चूंकि हर काम में अधिकारियों/इंजीनियरों द्वारा कमीशन लिया जाता है। स्वीकृत राशि का बहुत कम हिस्सा वास्तव में काम पर खर्च होता है। अतः, पुल सड़क टूटने का कारण कमीशन की नीयत ही है। इसके विपरीत रियासत कालीन निर्माण आज भी ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं।

सैटेलाइट से आजकल किसी भी क्षेत्र पर निगरानी संभव है। इसके बावजूद यदि वन क्षेत्र में कटाई हो रही है, नदी के बहाव में अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध खनन निरंतर बढ़ रहा है, पहाड़ कट कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार केवल एक ही बात को माना जा सकता है, वह यह कि संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अच्छी नीयत के साथ काम नहीं कर रहे हैं।

अधिकांश लोक सेवक, वे मंत्री ही चाहे अधिकारी, इस उद्देश्य से इस क्षेत्र में नहीं आते हैं कि उन्हें जनता के हित के साधन में माध्यम बनना है। कई बार तो लगता है कि उनकी नीयत सामान्य जनता को प्रताड़ित और परेशान करके धनोपार्जन की है। वे 'लोक सेवा' में आए ही इसलिए हैं कि वे जनता से अधिकाधिक सुविधा शुल्क वसूल कर सकें। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों हमारे शहरों की कच्ची बस्तियों में लोग नारकीय जीवन जीने के लिए अब भी अभिशप्त होते?

सवाल यह उठता है कि अच्छी नीयत वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या धीरे-धीरे कम क्यों होती जा रही है? उत्तर स्पष्ट है – समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रोत्साहन उन्हीं को मिल रहा है जो येन-केन-प्रकारेण अधिक संपत्ति और धन अर्जन कर लेते हैं। स्वाभाविक है, जो अच्छी नीयत से काम करते हैं वे जनता की दुआएं भले ही प्राप्त कर लें किंतु संपन्न नहीं बन सकते। युवा पीढ़ी, जब गलत मानसिकता से काम करने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित होते हुए देखती है तो वह भी वैसा ही करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है।

हाल ही में संचालित की जा रही एम आई आर की प्रक्रिया के लिए भी कहा तो यही गया कि यह मतदाता सुचियों के शुद्धिकरण के लिए है, किंतु वास्तव में इसका छद्म उद्देश्य कुछ विशेष वर्ग के लोगों को मतदाता सुचियों से बाहर करने का ही था। चुनाव आयोग संस्था तो संवैधानिक है, किंतु उसने सत्ताधारी दल के इशारे पर ऐसा किया, यह मानना गलत नहीं होगा। साफ है इस पूरी प्रक्रिया के पीछे लिखित उद्देश्य कुछ भी हो किंतु लागू करने वालों की नीयत में तो खोत है ही।

इसी प्रकार, सरकार ने शासन में नैतिकता और शुचितता लाने के उद्देश्य से संसद में एक विधेयक, 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले मंत्रियों/मुख्यमंत्रियों/प्रधानमंत्रों को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत किया, किंतु विपक्ष इसे विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने की नीयत से लाया गया बता रही है। वैसे भी यह पारित होना संभव नहीं लगता क्योंकि इसके लिए संसद में दो तिहाई बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है।

संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि सुशासन तब ही संभव है जब उसे लागू करने वाले सरकारी कर्मचारियों, विशेष कर उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्री और अधिकारियों की नीयत साफ हो । उनकी नीयत जनता का भला करने की हो, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि की नहीं। वर्तमान में तो सभी दल एवं अधिकांश नौकरशाह मिलकर जनता के पैसे को अपनी कमाई का माध्यम समझ कर ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी नीयत वाले लोगों के हाथ में प्रशासन और शासन सौंप बिना सुशासन की बात कौरी कल्पना ही रहेगी, चाहे कितने ही नियम क्यों न बना लिए जाएं।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. सुबोध अग्रवाल

थार के रेगिस्तान और दूर-दूर तक रेत के धोरों के लिए पहचाना जाने वाला राजस्थान आज औद्योगिक निवेश की विपुल संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश हो गया है। औद्योगिक निवेश के लिए देसी-विदेशी निवेशकों के लिए राजस्थान प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसे कभी निवेश के लिए बाधा माना जाता था, आज अवसरों का पिटारा बन गया है। थार का रेगिस्तान अब केवल रेत का विस्तार नहीं, बल्कि सौर और नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बन गया है। प्रदेश हरित विकास का नया अध्याय लिख रहा है तो धरती की गर्भ में छिपी खनिज संपदा ने राजस्थान में खनन विकास की नई इबारत लिखना शुरू कर दिया है। गत दिसंबर, 24 में आयोजित राईजिंग राजस्थान इसका जीता-जागता उदाहरण है कि आरआर समिट के दौरान ना केवल देसी-विदेशी निवेशकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया अपितु समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हस्ताक्षरत किये हैं। यह

आज के बदलते राजस्थान की तस्वीर है।

राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा को चार महत्वपूर्ण आयामों में विभाजित कर आसानी से समझा जा सकता है। एक थार के रेगिस्तान से नवीन अवसर तक: सौर और पवन ऊर्जा राजस्थान को हरित ऊर्जा केंद्र बना रही है। दूसरा, बंजर भूमि से औद्योगिक विकास तक: बाड़मेर आज प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी है और जैसलमेर भारत की सीमेंट राजधानी के रूप में उभर रहा है। तीसरा, चुनौतियों से ताकत तक: कोटा के जल संसाधन ऊर्जा भंडारण और शिक्षा हब दोनों को गति दे रहे हैं। तो चौथे, खनिज संपदा से आर्थिक शक्ति तक: पोटाश, यूरेनियम, हाइड्रोकार्बन, क्रिटिकल मिनरल और अन्य खनिज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय कर रहे हैं।

इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनने का बड़ा कारण यह है कि राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख केन्द्रों से कनेक्टिविटी और यहां की कानून व्यवस्था व लोगों का व्यवहारा शांति, सद्भाव और सहजता राजस्थान की पहचान है। मानव संसाधन की सहज उपलब्धता उद्यमियों के लिए और अधिक आसान हो जाती है। कहा जाता है और कुछ हद तक सही भी है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार नौकरी या किसी अन्य कारण से रहने के लिए आने वाला फिर यहीं का होकर रह जाता है। राजधानी दिल्ली से सबसे निकटतम शांत और बेहतर कानून व्यवस्था वाला प्रदेश राजस्थान है। एनसीआर का विस्तार राजस्थान और इसकी सीमाओं से लगते हुए हो रहा है। एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे के विस्तार से प्रदेश के किसी भी कोने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

आज देश में नवीकृत उर्जा के उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है तो अब सोलर के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करने वाले उद्योगों को भी राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बालोतरा के पचपदरा में तैयार हो रही हिन्दुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी शुरू होते ही तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। यहां पर पेट्रोकेमिकल जोन विकसित किया जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर जिसे कभी काले पानी की सजा के रूप में देखा जाता था तेजी से विकसित क्षेत्र होते जा रहे हैं। लगभग असंभव को संभव बनाते हुए बाड़मेर के विकास को इसी से समझा जा सकता है कि आज राजस्थान में परकेपिटा आय में बाड़मेर शीर्ष स्थान पर आ गया है।

बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से बीकानेर तक तपती धरती आज नवीकृत उर्जा खासतौर से सोलर उर्जा के उत्पादन बढ़ा रही है। नवीकृत उर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में अभी भी संभावनाओं को इसी से समझा जा सकता है कि 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में करीब करीब 8० प्रतिषत निवेश प्रस्ताव नवीकृत उर्जा क्षेत्र के प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार रीको के माध्यम से भूमि भी उपलब्ध कराने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2०24 के तहत आकर्षक प्रोत्साहन भी दे रही है। सिंगल विण्डो सिस्टम से निवेशकों के लिए राजस्थान में उद्योगों की स्थापना आसान हो रही है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के प्रति मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सरकार को गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वयं बड़े प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए हो रही प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह अपने स्तर पर कर रहे

हैं। मुख्य सचिव स्तर पर 2०0 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा प्रति सप्ताह की जा रही है तो इससे कम के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा नियमित रूप से संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। यह सब राजनीतिक ईच्छा शक्ति से ही संभव हो पा रहा है।

योजनाबद्ध प्रयासों से प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बाड़मेर-जैसलमेर को जहां राजस्थान में काले पानी की सजा से कम नहीं माना जाता था, आज वही बाड़मेर प्रदेश में परकेपिटा के हिसाब से शीर्ष पर आ गया है तो वो दिन दूर नहीं जब जैसलमेर सीमेंट के उत्पादन में देश की राजधानी बन जाएगा। पचपदरा में रिफाइनरी अब आ रही है पर इससे पहले ही बाड़मेर और आसपास के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से तेजी से विकास हुआ है। इस सबके पीछे एक बड़ा कारण तपती धरती को वरदान में बदलकर नवीकृत उर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रदेश में खनिजों की विपुल संपदा को एक्सप्लोर करने से संभव हो पाया है।

वैसे राजस्थान में सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के योजनाबद्ध प्रयास किये जा रहे हैं। कोटा में पानी की प्रचुरता के कारण नवीकृत उर्जा को संरक्षित कर उपयोग करने की विपुल संभावनाएं हो गई हैं तो शिक्षा नगरी के रूप में कोटा की अलग पहचान बन चुकी है। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विपुल भण्डार मिलने के साथ ही कच्चे तेल और गैस के भण्डार मिलने से पूरा सिनेरियो ही बदल रहा है। बीकानेर में पोटाश के विपुल भण्डार है तो राजस्थान में यूरेनियम के साथ ही क्रिटिकल मिनरल, गारनेट आदि आदि बहुतायत में है। राजस्थान की धरा के गर्भ में अथाह और विविध प्रकार की

खनि संपदा है।

सोने-चांदी और लेड जिंक सहित कई मिनरलों में तो राजस्थान शीर्ष पर आ गया है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन गया है। देसी-विदेशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद राजस्थान बनता जा रहा है। राजस्थान के सेंड डून्स, गढ़-किले से लेकर मंदिर गलियारें पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटन के कारण होटल व्यवसाय ने तेजी से विस्तार किया है तो जयपुर और राज्य के अन्य प्रदेशों तक सहज पहुंच के चलते आज राजस्थान मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी तेजी से पहचान बनाता जा रहा है। हेरिटेज होटलों के साथ सभी आर्थिक वर्ग की पहुंच को होटल्स की उपलब्धता है। राजधानी दिल्ली के नजदीक होने से दिल्ली आने वाला और नहीं तो जयपुर का ही चक्कर लगा लेता है। राजस्थान के एंटीक और रत्न व्यवसाय की धमक समूची दुनिया में है। औद्योगिक निवेशोन्मुखी माहौल का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि राजस्थान में जापानी जोन अलग से विकसित है और सफलता पूर्वक औद्योगिक उत्पादन हो रहा है।

देखा जाए तो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में संसाधन होने के साथ ही राज्य सरकार की स्पष्ट उद्योगोन्मुखी नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और निवेशक-अनुकूल माहौल भी है। यही कारण है कि राजस्थान आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि का घुरी बनता जा रहा है। आने वाला समय राजस्थान का है और राजस्थान अब केवल पर्यटन ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, खनिज, शिक्षा और उद्योगों का केंद्र भी हो गया है।

—डॉ. सुबोध अग्रवाल, (आईएएस) अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

मंगला आरती के साथ 641वें रामदेवरा मेले का विधिवत शुभारंभ

- प्रदेश सहितज अनेक राज्यों से आये हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेवजी की समाधि के दर्शन कर मन्त्र मांगी
- प्रशासन के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने बाबा की समाधि पर पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन कर स्वयं को धन्य माना। कई श्रद्धालु दर्शन के लिए रातभर कतार में खड़े रहे। अलसुबह मंदिर के मुख्य द्वार खुलते ही बाबा के जयकारों की गूंज से निज मंदिर परिसर उत्साह और श्रद्धा से भर उठा। मंदिर परिसर, गलियों और आसपास के क्षेत्रों में नगाड़ों और लोक भजनों की मधुर ध्वनि गूंजती रही।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी लाखा राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सेन, विकास अधिकारी हनुमान राम, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान, बाबा वंशज गदीपति भोमसिंह तंवर, सांकड़ा पंचायत समिति के प्रधान



लोकदेवता बाबा रामदेवजी की समाधि के भक्तों ने दर्शन किये।

खेतों में पानी की डिगियों में सैकड़ों मछलियों की मौत

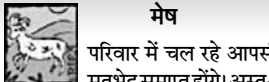
श्रीगंगानगर, (निर्सं)। जिले के केसरीसिंहपुर करुबे के पास गांव 16-17 एक जंघातिया में किसानों की कृषि भूमि में बनी पानी की डिगियों में अज्ञात कारणों से भारी संख्या में मछलियां मरने लगी हैं। सोमवार सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो डिगियों की सतह पर सैकड़ों मरी हुई मछलियां और बाकी को तड़पते हुए देखा गया।

यह नजारा देखकर किसानों में चिंता की लहर दौड़ गई।

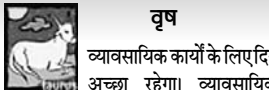
गांव के किसान लखविंदर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह जब वे खेत में पहुंचे तो डिग्गी की सतह पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखीं। वहीं सैकड़ों मछलियां ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने आशंका जताई कि किसी अज्ञात व्यक्ति

द्वारा डिगियों में जहरीली दवा या रसायन डाला गया हो सकता है, जिससे

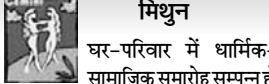
यह स्थिति उत्पन्न हुई। घटना की सूचना मिलने पर वेटरनरी विभाग के डॉक्टर महावीर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और डिग्गी का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रारंभिक जांच के आधार पर किसान की आशंका को खारिज करते हुए बताया कि मछलियों की मौत का



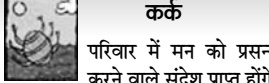
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



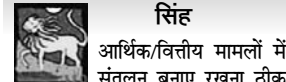
वृष व्यावसायिकों के लिएदिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



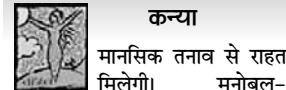
मिथुन घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समस्याएं हल हो सकती हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



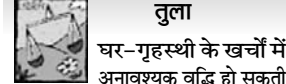
कर्क परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी, उचित सफलता मिलेगी।



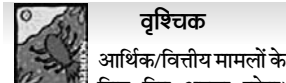
सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।



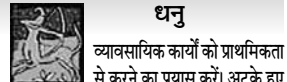
कन्या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



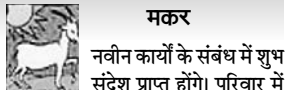
तुला घर-गृहस्थी के उखड़ों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।



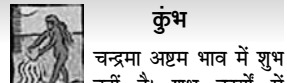
वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।



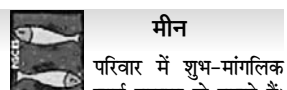
धनु व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अकेले हुए कार्य शीघ्रता/सुप्रभा से बने लेंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चन दूर होने लेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।



मकर नवीन कार्य के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ चंद्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।



मीन परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।